श्री महेन्द्र मोहन: सर, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी यह देखेंगी कि दूरदर्शन के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स का जो सजीव प्रसारण दिया जाएगा, वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हो, लेकिन इसके साथ-ही-साथ मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या दूरदर्शन के अलावा कुछ अन्य प्राइवेट चैनल्स भी इसका प्रसारण करेंगे या केवल दूरदर्शन के ही सारे चैनल्स इसका प्रसारण करेंगे?

श्रीमती अम्बिका सोनी: सर, भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स की Organizing Committee ने प्रसार भारती के साथ host broadcaster का Mou Sign किया था। भारत में सिर्फ दूरदर्शन के द्वारा coverage दिखाई जाएगी। दूरदर्शन के 31 चैनल्स हैं, जो यह coverage दिखाएंगे। लेकिन international level पर Organizing Committee ने broadcasting के rights दूसरी विदेशी कंपनियों को दिए हैं।

Coal scam in Orissa

*302. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the Minister met agitating MLAs sitting on dharna in the Orissa Legislative Assembly over coal scam and assured them that the Central Government would refer it to the Central Bureau of Investigation (CBI);

(b) if so, whether Government has received State Government's report in this regard;

(c) whether Government has taken initiative of entrusting the case to CBI as recommended by the State Government; and

(d) if not, the other steps Government proposes to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Minister of State for Coal (I/C) met agitating MLAs sitting on dharna in the premises of Orissa Legislative Assembly alleging diversion of coal allotted to the State of Orissa. The Minister stated that Central Government has no role in distribution of coal allotted to the State Government nominated agency and it is the responsibility of the State Government to ensure that the

coal reaches the eligible consumers. The Minister had assured them that in the event the State Government requested the Central Government for a reference to CBI, the same would be considered. However, no such request has been received from the State Government in this regard.

(c) and (d) Does not arise in view of (a) and (b) above.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, in his reply the hon. Minister said that the State Government of Orissa had not recommended for CBI inquiry and that is why the Central Government has no power. The illegal mining and coal scam in Orissa has greatly affected the power projects in the country. Illegal mining of coal is taking place and it is causing losses to the Government. It being a State subject, has the Union Government urged the State Government to take immediate steps to check coal scam in Orissa?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय सदस्य ने दो तरह के प्रश्न किए हैं। एक प्रश्न इल्लीगल माइनिंग से संबंधित है और दूसरा कोल स्कैम से संबंधित है। जहां तक कोल स्कैम की बात है, 2007 से पहले हमारी कोल कंपनीज फुटकर विक्रेताओं को, ईंट-भट्ठे वालों को, समय-समय पर कोलया दिया करती थीं। 2007 में NCDP के नाम से एक कोल पॉलिसी बनाई गई, जिसमें फुटकर विक्रेताओं को, ईंट-भट्ठे वालों को और जिनको भी फुटकर कोयले की आवश्यकता होती थी, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को यह ऑथोराइज किया गया कि वे अपने द्वारा नॉमिनेटिड एजेंसीज के माध्यम से उस कोयले का वितरण करें। स्टेट गवर्नमेंट्स को हम, जो उनकी आबंटन की क्वांटिटी है, उतना कोयला दे देते हैं और वे स्वयं अपने-अपने स्टेट्स में, जहां-जहां फुटकर कोयले की आवश्यकता होती है, उनको कोयला देती हैं।

दूसरा प्रश्न आपने उड़ीसा कोल स्कैम के बारे में पूछा है। जब मैं उड़ीसा, सम्बलपुर गया था, तो सम्बलुपर से लौटते समय भुवनेश्वर पहुंचने पर मुझे पता चला कि बहुत सारे विधायक इस बात की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं कि एक बहुत बड़ा कोल स्कैम हुआ है, जिसमें स्टेट द्वारा नामित एजेंसी के माध्यम से कोयले का डायवर्जन किया गया है। मैं उन विधायकों से मिला और उनसे पूरी बात पूछी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, मैंने भी उनसे कहा कि हां, इसकी जांच होनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास कोई रिक्वेस्ट भेजती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे कंसिडर करेगी।

इनका दूसरा प्रश्न, जो इल्लीगल माइनिंग से संबंधित है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप एक ही सवाल का जवाब दीजिए।

SHRI V. HANUMANTHA RAO: In view of the large scale illegal mining in the country, has the Government decided to set up a National Mining Regulator for major minerals such as coal and iron

ore which would help in tackling the growing menace of illegal mining, and whether the Regulator will be, more or less, like TRAI and SEBI and will be an independent quasi-judicial body with powers to order investigation and also prosecution? To what extent, will it help in checking illegal mining?

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I have a point of order. This does not have any connection with the question.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह माइनिंग से संबंधित है, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग से ही यह प्रश्न करना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग इल्लीगल माइनिंग के लिए पूरे देश में क्या कर रही है। अगर आप परमिशन दें तो कोल की इल्लीगल माइनिंग के बारे में...(व्यवधान)...

श्री वी. हनुमंत राव: आप कोल माइनिंग के बारे में ही बताइए, माइनिंग के बारे में छोड़ दीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, जहां तक कोल की इल्लीगल माइनिंग की बात है, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है, अगर हमारी माइन के अन्दर कोई इल्लीगल माइनिंग करने की कोशिश करता है, जो कि आम तौर पर नहीं होता है। वैसे कोल प्रॉपर्टी पूरे देश में फैली हुई है। कई स्टेट्स में कोल प्रॉपर्टीज हैं...(व्यवधान)...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I have raised a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just one minute. ...*(Interruptions)*... Let us hear his point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री वी. हनुमंत राव: सर, क्वेश्चन आवर में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नही होता।

MR. CHAIRMAN: Just one minute. ...*(Interruptions)*... I know the position. ...*(Interruptions)*... Let's stick to the question. ...*(Interruptions)*...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: It is only about the question. The Minister has replied ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He has not said anything. ...*(Interruptions)*...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: The Minister has replied about coal scam in Orissa saying that he met some legislators. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That is all right. ...*(Interruptions)*...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: It is not something which has been asked. This is ...*(Interruptions)*...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: The State Government is not recommending for a CBI inquiry. ...*(Interruptions)*...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: It is not part of the question.

MR. CHAIRMAN: You will get your turn to put your supplementary question. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: If there is no scam, then, why is the Chief Minister not recommending to the Central Government for a CBI inquiry?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर, पहले तो प्रश्न काल में कोई point of order होता ही नहीं...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपने सही कहा।...(व्यवधान)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अगर कोई point of order है, तो उनको रूल कोट करना चाहिए कि under which rule, he is asking.

MR. CHAIRMAN: Fair enough.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, जहां तक कोल की illegal mining का प्रश्न है, उसमे मैंने पहले भी कहा है और मै फिर यह बात कहना चाहता हूं कि माइन्स के अंदर से illegal mining नही होती है, बल्कि coal bearing States मे जो coal properties पड़ी हैं, वहीं illegal mining होती है। इसके लिए हम समय-समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, क्योंकि पुलिस और law and order स्टेट का सब्जेक्ट है। illegal mining को रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का ही है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स से कहते रहते है कि आप illegal mining को रोकने के लिए जो भी संभव उपाय हो सके, करिए। हमारे मुल्क में illegal mining होती है, इससे हम इंकार नहीं करते हैं। illegal mining को रोकने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। हम भी प्रयास करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रयास करती हैं, इससे हम इंकार नहीं करते हैं।

श्री वी. हनुमंत राव: सर, illegal mining में ...**(व्यवधान)**... स्टेट गवर्नमेंट्स वाले भेजते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले देखते रहते हैं...(व्यवधान)... ओबुलापुरम में क्या हो रहा है, सर...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: You have asked your question; you have asked your supplementary. Now, Shri Mohapatra.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, the Congress and BJP Members of the Orissa Legislative Assembly had gathered outside the Assembly for days together demanding an inquiry into, what they said, the coal scam. ...*(Interruptions)*... You cannot stop me. ...*(Interruptions)*... Please, don't shout, I am addressing the Chair.

MR. CHAIRMAN: What is the supplementary question?

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I am coming to the supplementary. Is it a fact. ...*(Interruptions)*... They were alleging about irregularities in distribution of coal to micro, small and medium industries by the Orissa Small Industries Corporation and by the Orissa Consumer Co-operative Federation. Now, is it a fact that the Minister went there, or, was invited over there? Newspaper report suggested that. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद अली खान: सर,...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, resume your places.

श्री मोहम्मद अली खान: सर, रूल्स तो सब के लिए हैं...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए।

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Is it a fact, as reported in the newspaper, that the Minister assured them that he would get a CBI inquiry done, or, he assured them that their allegations regarding coal scam were correct?

MR. CHAIRMAN: I think, he has already replied to that.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: No, he has not replied to either of that.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, हम इसमें थोड़ा डिटेल में भी बताना चाहते हैं, अगर आप परमिशन दें।

माननीय सदस्य ने आधी बात तो वही कही है, जो मैंने कही है, लेकिन आधी बात में शायद इनको भ्रमित किया गया है और इनको सही सूचना नहीं है। बहुत सारे विधायक जो वहां धरने पर बैठे थे, उन्होंने हमको कॉल किया कि सर, एक बहुत बड़ा स्कैम उड़ीसा में हुआ है। मैंने उनको बताया कि हम फुटकर विक्रेताओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कोटा निर्धारित कर देते हैं और वह कोटा हम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भेज देते हैं। अब यह

जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है कि वे फुटकर विक्रेताओं के लिए कोल का डिस्ट्रिब्यूशन करें। अगर उसमें कोई घोटाला हुआ है, तो इसकी जॉच स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। उन लोगों ने हमसे कहा कि इसकी सी.बी.आई. जांच करवाई जाए। इस पर मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि इस मामले की सी.बी.आई. जॉच हो, तो उन्हें चाहिए कि वह भारत सरकार के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजें, हम उसको कंसीडर करेंगे। इससे ज्यादा और कोई बात नही हुई है। अगर इससे ज्यादा आपको पता है, तो मुझे लगता है कि आपको भ्रमित किया गया है।

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Mr. Chairman, Sir, the distribution of coal is a Central Government subject. The coal, which was given for distribution to the Orissa Small Industries Corporation and also to the Orissa Consumer Co-operative Federation, was given by the Coal Department of the Central Government. I want to know whether the recommendations of the State Government were not required as the allotment of coal was done by the Government of India. Will the Central Government consider for a CBI inquiry even if the State Government has not recommended for the CBI inquiry?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, मैंने इस माननीय सदन को पहले ही बताया है और आपसे यह अनुरोध किया है कि न्यू कोल डिस्ट्रिब्यूशन पॉलिसी के तहत फुटकर विक्रेताओं और फुटकर उपभोक्ताओं के लिए भारत सरकार की जितनी subsidiary कोल कंपनियां हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट्स को इससे संबंधित कोटा अलॉट कर देती है और यह उन स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे उन लोगों को कोल वितरित करें। इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं होता है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स से इस बात की शिकायतें समय-समय पर आती रहती हैं कि कोल-डिस्ट्रिब्यूशन सही नहीं हो रहा है, लेकिन यह स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे कोल डिस्ट्रिब्यूशन को सही ढंग से करायें जिससे कि उपभोक्ता पूरे तरीके से संतुष्ट हो सकें।

SHRI Y.S. CHOWDARY: Sir, the Karnataka Government have already banned exports of iron ore. I want to know whether the Central Government is similarly planning to have any such ban on iron ore or coal.

MR. CHAIRMAN: Please stick to the question. It is a specific question. Do you have any supplementary on this or not?

SHRI Y.S. CHOWDARY: Yes, Sir. Is there any plan of the Central Government to allocate coal only for manufacturing units rather than for traders?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मैंने दो बार जवाब दिया है कि ट्रेडर्स के लिए, फुटकर उपभोक्ताओं के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट्स को कोटा दे देते है और यह स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे अपने द्वारा नॉमिनेटेड एजेंसीज के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए जहां चाहे वहां कोयले का आबंटन करें। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारी कोल कंपनियों की कोई भूमिका नही है।

GoM on mining issues

*303. SHRI K.N. BALAGOPAL: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether a Group of Ministers (GoM) is working on mining sector issues; and

(b) if so, the details of major issues which are under consideration?

THE MINISTER OF MINES (SHRI B.K. HANDIQUE): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government has constituted a Group of Ministers on 14th June, 2010 with the specific term of reference of considering the draft Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill 2010 and giving its recommendations in the matter. The draft Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill 2010, has been prepared on the basis of policy directions in the National Mineral Policy, 2008, and Hoda Committee recommendations after an intensive exercise of consultation with all the stakeholders including representatives of civil society concerned with environmental/societal impact. The major issues laid down in the National Mineral Policy, 2008 and Hoda Committee recommendations, and considered in the draft Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill 2010 *inter-alia* include:

(i) making the regulatory mechanism more conducive to technology and investment flows and providing security of tenure to concessionaires.

(ii) ensure transparency, seamlessness and security of tenure in the concession process.